कौन बेहतर मायावती या मुलायम सिंह ?

नई-दिल्ली: राजनीति में दो कदम ही सही साथ चलने वाले मुलायम और माया के बीच आजकल 'कौन बेहतर' की जंग छिड़ी है। यह और बात है कि जनता, जिसने कई बार माया-मुलायम की सरकार झेली है, वह दोनों की

सरकारों को नकारती रही है। मुलायम राज में जहां छोटे से छोटा सपा नेता अपने आप को मिनी सीएम समझता था, वहीं सपा कार्यकर्ता 'दबंग' रूप में दिखते थे। बात-बात पर मारपीट करना और धमकी देना सपाइयों की दिनचर्या में शामिल हो गया था। सपा नेताओं का आलम यह था कि उस समय दिल को दहला देने वाले निठारी कांड को भी सपा नेताओं ने मामूली घटना करार दे दिया। यह तो अपवाद भर था।

बसपा सरकार का चेहरा भी करीब-करीब ऐसा ही है। भले ही वह मुलायम सरकार के जंगलराज का ढिंढोरा पीट कर सत्ता में आई थी, लेकिन मायावती के राज में बसपाई निरंकुश दिखते रहे। क्या नेता, क्या कार्यकर्ता, सभी मनमानी पर उतर आए। बसपा और सपा में फर्क इतना था कि बसपा में कभी सत्ता का दूसरा कोई केन्द्र नहीं हुआ जैसे कि मुलायम राज में शिवपाल यादव, अमर सिंह, रामगोपाल यादव समानान्तर सरकार चलाते थे। माया राज में उसी जनप्रतिनिधि/नेता/कार्यकर्ता की चली जिसके सिर पर जितने दिनों तक बहनजी का हाथ रहा। बात चाहे आपराधिक कृत्य के कारण जेल की हवा खा रहे बसपा विधायक आनंद सेन यादव की हो या फिर बांदा के विधायक पुरूषोत्तम द्विवेदी अथवा इंजीनियर हत्याकांड में जेल की सलाखों के पीछे पड़े शेखर तिवारी आदि की। इसी प्रकार भ्रष्टाचार की गंगा में गोते लगाने वाले मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा, अनंत मिश्र जैसे तमाम नेताओं को मायावती ने जब तक चाहा अपने 'रत्नो' में शामिल रखा बावजूद इसके कि भ्रष्ट मंत्रियों को हटाने के लिए विपक्षियों ने मायावती पर कई बार दवाब बनाया था। माया ने जब स्वयं ही समझा तब दागी मंत्रियों को 'दूध की मक्खी' की तरह निकाल कर बाहर फेंका। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया।

मायावती, पर भी मुलायम सिंह की तरह भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे। दोनों के खिलाफ कुछ मामले अदालत में चल रहे हैं। इसमें प्रमुख रूप से आय से अधिक संपत्ति का मामला है, जिसकी चपेट में दोनों ही नेता हैं। बात विकास की कि जाए तो दोनों ने ही विकास के नाम पर अपना एजेंडा आगे बढ़ाया। मुलायम राज में उत्तर प्रदेश विकास परिषद का गठन हुआ। अमर सिंह को इस परिषद की कमान सौंपी गई। विकास के नाम पर अपनों को माला-माल करने की कड़ी में मुलायम ने अमर सिंह के कहने पर कई ऐसे फैसले लिए जो तर्कसंगत नहीं थे। अमर के कहने पर मुलायम ने अमिताभ बच्चन को उत्तर प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उस समय अमर और अमिताभ की अच्छी खासी घनिष्टता थी। अनिल अंबानी को दादरी में बिजली प्लांट लगाने के लिए किसानों की जमीन कौड़ियों के दाम देने की कोशिश हुई। इसके खिलाफ पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह को धरना तक देना पड़ा था। बाद में माया सरकार की मंशा और कोर्ट के आदेश ने मुलायम के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को हासिए पर पहुंचा दिया। बाद में अनिल अंबानी ने इस प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिए। मुलायम राज में अनिल अंबानी जैसे उद्योगपति और अमिताभ बच्चन तथा अमर सिंह सरीखे लोगों को उनका करीबी समझा जाता था। वहीं माया राज में इस जगह की भरपाई सतीश मिश्र, जेपी ग्रुप जैसे लोगों ने की। वाइन किंग पोंटी चद्दा का सिक्का दोनों ही राज में चला।

मायावती दलित महापुरूषों और बाबा साहब अम्बेडकर तथा कांशीराम आदि के नाम पर पैसा पानी की तरह बहा रही हैं। पार्कों का निर्माण प्रदेश में उद्योग सरीखा बन गया है। इससे माया के कई करीबी मालामाल हो रहे हैं। वहीं मुलायम शासन में ट्रांसफर-पोस्टिंग उद्योग बन गया था। उनके समय में चपरासी और सिपाही से लेकर बड़े-बड़े पदों पर मौजूद पुलिस अधिकारियों और नौकरशाहों का तबादला 'नेग' चढ़ाने के बाद ही हो पाता था। मुलायम के मंत्रियों के पास ट्रांसफर-पोस्टिंग चाहने वालों की लिस्ट हमेशा मौजूद रहती थी। माया ने सत्ता में आते ही इस परम्परा को पूरी तरह से बंद कर दिया। अव्वल तो बड़े पैमाने पर तबादला होता ही नहीं है और अगर होता भी है तो मुख्यमंत्री को इसकी पूरी जानकारी रहती है। किसी मंत्री को यह अधिकार नहीं मिला हुआ है। माया के मंत्रियों ने कमाई के नए रास्ते तलाश लिए। यही वजह थी माया राज में स्कूल-कालेजों को मान्यता दिलाने को खेल खूब फलाफूला।

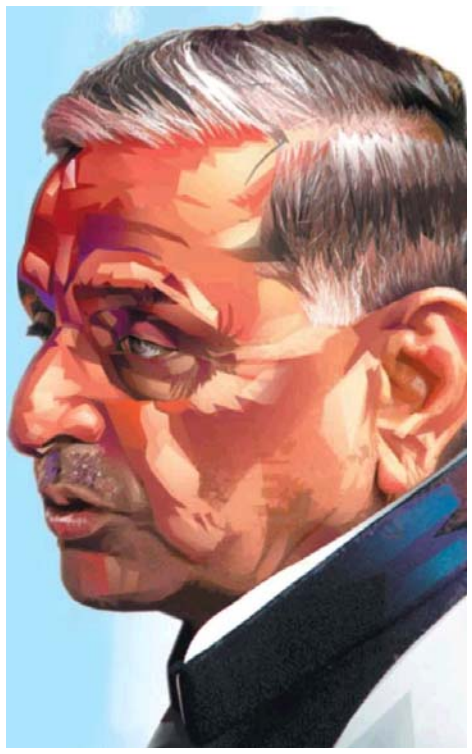

किसान राजनीति में भी दोनों नेता करीब-करीब एक ही प्लेटफार्म पर खड़े हैं। पहले मुलायम ने किसानों को अपने लिए इस्तेमाल किया, अब यही काम मायावती कर रही हैं। गन्ना मूल्य में वृद्धि कर किसानों को खुश करने का खेल दोनों ने ही खूब खेला। चीनी मिलों से मोटी कमाई में भी दोनों ही सरकारों में होड़ लगी रही।

बात ताजा मामलों की कि जाए तो निकाय चुनाव कराने के मामले में भी दोनों का रुख एक जैसा था। मुलायम भी अपने शासनकाल में निकाय चुनाव कराने के मूड में नहीं थे, बाद में कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उन्हें निकाय चुनाव कराना पड़ा। वर्तमान में निकाय चुनाव कराने के लिए माया सरकार पर अदालतों का जबर्दस्त दबाव है। वह भी चुनाव न कराने के लिए ना-नुकुर कर रही हैं। मुलायम को अपने शासनकाल में निकाय चुनाव ही नहीं अन्य कई मामलों में भी अदालत की फटकार सुननी पड़ी थी। ऐसा ही कुछ हाल मायावती सरकार का है। पार्कों के निर्माण, एक्सप्रेस हाईवे, भूमि अधिग्रहण सहित कई मामलों में बसपा सरकार अदालतों का चक्कर लगा रही है।